डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जनवरी, 2021, डिस्पेच दिनांक 16 जनवरी, 2021

| वर्ष 64 | अंक 16 | भोपाल | 16 जनवरी, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

जिले बनाएं विकास योजनाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रत्येक जिले की पृथक विकास योजना बनाई जाए। आगामी एक अप्रैल से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। नगरों के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी विकास का प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने के साथ ही अच्छी कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। जिला विकास योजना के निर्माण के साथ ही सुशासन, आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, नागरिकों को समय पर आवश्यक सेवाएं देने, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सभी तरह के माफिया को नेस्तनाबूत करने की हमारी प्राथमिकता है। सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और शासन स्तर के अधिकारी इन लक्ष्यों के अनुकूल कार्य करते हुए परफार्म करें। अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाले ही पदों पर कायम रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में वर्चुअल कलेक्टर्स, कमिश्नर्स कान्फ्रेंस के प्रथम सत्र में कहा कि यह आवश्यक है कि राज्य में गुंडागर्दी, नक्सलवाद, तस्करी आदि की समाप्ति के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रयास हों। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मैदानी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रारंभ योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश को अव्वल रहना है। हमारे प्रयासों की पराकाष्ठा होना चाहिए ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हों।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी, अंधी गली में नहीं चलना है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को हर योजना में नंबर वन रहना है। जिलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में भी आगे रहना है। कलेक्टर्स भी स्थानीय स्तर पर जिले के विकास की योजनाएं बनाएं। हमें अंधी गली में नहीं चलना है।

योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग हो। कमिश्नर और आई.जी. भी अपने अधिकार क्षेत्र में सभी कार्यों पर नजर रखें। विकास का वार्षिक प्लान तैयार करना है। एक अप्रैल से इस प्लान पर चलना है। हर माह समीक्षा होगी। इसी आधार पर जिले की रेटिंग होगी, विभागों की भी रेटिंग होगी। उन्होंने कहा कि हमें राजस्व भी बढ़ाना है। धनराशि की कमी का तर्क नहीं चलेगा। जिलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

समर्थन मूल्य पर धान और अन्य अनाज की खरीदी

कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान मिलिंग के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 37 लाख से ज्यादा बालिकाएँ लाभान्वित

भोपाल। प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति मे सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधार शिला रखने के उददेश्य से लाडली लक्ष्मी योजना अप्रैल 2007 से लागू की गई थी। इस योजना के प्रारंभ से दिसम्बर 2020 तक लगभग 37 लाख 63 हजार 735 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 2 लाख 28 हजार 283 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत किया गया। इस शैक्षणिक वर्ष में कक्षा–6, कक्षा–9 एवं कक्षा–11 में प्रवेश लेने वाली कुल एक लाख 53 हजार 917 बालिकाओं को 39.06 करोड़ रूपये का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जा चुका है।

योजना अंतर्गत प्रकरण स्वीकृति के बाद हितग्राही बालिका को एक लाख 18 हजार रूपये का प्रमाण–पत्र प्रदाय किया जाता है तथा बालिका के नाम से लगातार 5 वर्ष तक 6000–6000 की राशि (कुल 30000) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि में अंतरित की जाती है।

लोक सेवा गारंटी से प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही तय हुई है-मंत्री डॉ. भदौरिया

ग्रामों का भ्रमण कर लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल हुए

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम सुशासन की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई है, बल्कि जवाबदेही तय हुई है। अब लोगों को समय–सीमा में सेवाएँ भी मिल रही हैं। मंत्री डॉ. भदौरिया शनिवार को भिण्ड जिले की ग्राम पंचायत खड़ेरी, खड़ीत, शुक्लपुरा, मोंधना एवं कनेरा गाँव में लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रमों में आमजनों को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अभी 47 विभाग/संस्थाएँ हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम से पहले लोगों को आय, जाति प्रमाण–पत्र जैसे कार्यों के लिये सरकारी कार्यालयों में भटकना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को मोबाइल के माध्यम से वाट्सअप पर ही घर बैठे आय और जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो जाएँगे। इसके लिये आवेदक को केवल आधार नम्बर की जानकारी देनी होगी।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि नये कृषि कानून कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हैं। उन्होंने कहाकि नये कृषि कानून मण्डियों के अलावा राज्य के भीतर एवं बाहर किसी भी स्थान पर किसानों को उनकी उपज बेचने के अवसर प्रदान करेंगे। अब किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिल सकेगी।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को 3 किश्तों में दी जाने वाली 6 हजार रुपये की राशि के अलावा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत 2 किश्तों में 4 हजार रुपये अतिरिक्त राशि दी जा रही है। इस प्रकार किसानों को अब सम्मान निधि के तौर पर कुल 10 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण देने की योजना पुनरू शुरू कर दी है। मंत्री डॉ. भदौरिया ने किसान कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी।

कार्य ऐसा हो कि एक साल बाद लोग मध्यप्रदेश को दें बधाई

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नव वर्ष में, नव चिंतन कर कार्य योजना अमल में लाएं : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के पास कोलार वन विश्राम गृह में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए ऐसा कार्य हो कि एक वर्ष बाद मध्य प्रदेश को बधाइयां मिलें। उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए विभाग वार एक्सरसाइज कर अच्छे कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए।

अब तक किये कार्य जनता के हित की प्रतिबद्धता के परिचायक है; इन्हें जन समर्थन भी मिला

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बीते 9,10 माह में प्रदेश के विकास, प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आम जनता से भी सरकार के अनेक कार्यों के प्रति समर्थन प्रतिक्रिया मिली है। माफिया के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई और नशे से युवा वर्ग को बचाने के ठोस प्रयासों का अच्छा संदेश गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब मार्च के आखिरी सप्ताह में सरकार बनी तब कोरोना की बड़ी चुनौती सामने थी। इससे नागरिकों को बचाने का कार्य तत्परता से किया गया। प्रभावी कदम उठाए गए। वायरस के नियंत्रण के साथ ही सबसे पहले मध्य प्रदेश में आत्म निर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया गया।

आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति में मध्य प्रदेश ने पहले पहलकर बनाया रोडमेप

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जैसे ही प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही उनके चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए ठोस पहल की गई। सभी मंत्रियों, अर्थशास्त्रियों, नीति आयोग के पदाधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने विचार मंथन कर मध्य प्रदेश रोड मैप की तैयारी की। प्रयास सार्थक हुए। मध्य प्रदेश सबसे पहले यह रोड मैप बनाने में सफल हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अर्थव्यवस्था, रोजगार सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मुद्दों पर रोड मैप में विस्तार से कार्य का निर्धारण किया गया है।

राजस्व बढ़ाने का कार्य तेज हो

प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अच्छी राजस्व वसूली का कार्य कुछ प्रयासों से ही संभव है। इस दिशा में अच्छी उपलब्धि मिल रही है। विशेषकर जीएसटी कलेक्शन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से आगे है। राजस्व वृद्धि के प्रयास तेज किए जाएं।

मिली उपलब्धियां

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात हो या ग्रामीण विकास के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता, मध्यप्रदेश ने कुछ कार्यों में रिकॉर्ड बनाया है। देश में सबसे अधिक गेहूं उपार्जन किए जाने के बाद किसानों के खातों में राशि पहुंचाने का कार्य हुआ। प्रदेश में दो एक्सप्रेस–वे प्रगति पर हैं। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क से व्यापक पैमाने पर रोजगार की संभावनाओं को साकार किया जाएगा। बफर में सफर शुरू हो चुका है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तत्काल देने की व्यवस्था, किसानों को बिना चक्कर लगाए विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य प्रदेश में बखूबी किया जा रहा है। इसे और गति देना है। पत्थर बाजी पर प्रतिबंध के लिए कड़ा कानून बनाया जा रहा। धर्म स्वातंत्र्य कानून की प्रशंसा हुई है। अन्य नवाचार भी किए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश बने उदाहरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्री गण चिंतन कर विभाग की योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करवाएं। क्षमता का पूरा उपयोग कर बेहतर परिणाम दे सकते हैं। प्रयास होना चाहिए कि आने वाले एक वर्ष में हम बहुत सी उपलब्धियां अर्जित कर लें और सभी राज्य मध्यप्रदेश को बधाई दें। हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि मध्य प्रदेश अग्रणी स्थिति में आकर एक उदाहरण माना जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ परिणाम लाने की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रेत उत्खनन के संबंध में लागू की जा रही नई व्यवस्था की भी जानकारी दी, जिससे राजस्व आय बढ़ेगी। साथ ही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।

कोरोना वैक्सीनेशन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में की गई व्यवस्थाओं के बारे में बताया और मंत्री गण से इस कार्य में नेतृत्व एवं सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।

नव चिंतन कर कार्य योजना पर अमल हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शुरू में सभी मंत्री गण को नववर्ष की बधाई दी और नवचिंतन के साथ नवीन कल्पनाओं को साकार कर मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद की।

जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं
एक वो
जो सोचते हैं
लेकिन करते नहीं
दूसरे वो
जो करते हैं
पर सोचते नहीं

कार्यालय– आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र., भोपाल

क्रमांक/शि.प्रशि./2020/483 दिनांक 05/01/2021

प्रति,

(1)प्रबंध संचालक
शीर्षस्थ सहकारी संस्थायें (समस्त)
मध्यप्रदेश

(2)मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक
समस्त केन्द्रीय/ प्राथमिक सहकारी संस्थायें
मध्यप्रदेश

विषय : राज्य संघ को अभिदाय एवं अंशदान के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ : प्रमुख सचिव सहकारिता, म.प्र.शासन का निर्णय दिनांक 20.11.2020

विषयान्तर्गत म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग व्दारा राज्य सहकारी संघ को देय अभिदाय एवं अशदान के भुगतान के संबंध में लिये गये शासकीय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव सहकारिता व्दारा दिनांक 20.11.2020 को आयोजित समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयों का कृपया अवलोकन करें जिसमें अभिदाय एवं अंशदान के संबंध में व्याप्त भ्रम के निराकरण हेतु उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के तारतम्य में म.प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/2521–1774/15/1 भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 1977 का अवलोकन किया जावे (छायाप्रति संलग्न), जिसमें राज्य शासन व्दारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 30 में संशोधन कर अंशदान की दर धारा 43 की उपधारा के खण्ड– ब के अधीन किये जाने का लेख किया गया है। अतः स्पष्ट है कि धारा 43 की उपधारा 2 के खण्ड–ब के अधीन भुगतान किये जाने वाली राशि जिसकी दर नियम 30 के अनुसार निर्धारित है वह अंशदान है।

धारा 47 के तहत राज्य/जिला संघों को भुगतान की जाने वाली राशि जिसे कुछ विभागीय निर्देशों/परिपत्रों में चंदा, अभिदाय, सदस्यता अभिदाय आदि के रूप में संबोधित किया गया है वह मूलतः सदस्यता अभिदाय है जिसकी सम्बद्धता एवं दर का निर्धारण राज्य शासन व्दारा अधिसूचना जारी कर की जाती है। वर्तमान में सम्बद्धता एवं अभिदाय दर के संबंध में राज्य शासन का आदेश दिनांक 27 अप्रैल 1977 प्रचलन में है, जिसकी प्रति संलग्न है।

स्पष्ट है कि उपरोक्त मार्गदर्शन से समस्त संस्थाओं में अंशदान एवं अभिदाय के संबंध में उत्पन्न भ्रमों का निराकरण जावेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सहकारी संघ/जिला संघों को सदस्य संस्थाओं से अभिदाय/अंशदान का भुगतान प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर से पूर्व किया जाना वैधानिक रूप से अनिवार्य है जिसका पालन सुनिश्चित किया जावे।

सही/–
आयुक्त एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र.

क्रमांक/शि.प्रशि./2020/483 भोपाल, दिनांक 05/01/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1– प्रमुख सचिव सहकारिता, म.प्र. शासन, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
2– प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
3– कक्ष प्रभारी (समस्त) मुख्यालय।

सही/–
आयुक्त एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र.

प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान को नए सिरे से चलाया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान को नए सिरे से चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा तथा सशक्तीकरण हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। मध्यप्रदेश की पोषण नीति तैयार है, जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने गंभीर कुपोषित बच्चों का एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम राज्य में लागू किया है। हम कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करेंगे। हमारा ध्येय है ''पोषित परिवार–सुपोषित मध्यप्रदेश''।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह और प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल उपस्थित थे।

बच्चों का कुपोषण दूर करने के सघन प्रयास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत उनका नियमित रूप से वजन लिए जाना, पोषण आहार प्रदाय, सामान्य कुपोषित बच्चों का समुदाय स्तर पर उपचार एवं पोषण प्रबंधन, अतिरिक्त पोषण आहार प्रदाय, गंभीर कुपोषित बच्चों का पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर उपचार एवं देखभाल आदि कार्य किए जा रहे हैं। पोषण सेवाओं की मॉनीटरिंग के लिए ''पोषण डैशबोर्ड'' तैयार किया गया है।

पोषण स्तर में सुधार होने पर प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि ''पोषित परिवार–सुपोषित मध्यप्रदेश'' कार्यक्रम के अंतर्गत गंभीर कुपोषण वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने पर परिवार को प्रोत्साहन राशि दी जाती है तथा सम्मान किया जाता है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका

प्रदेश की 62 हजार 500 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका बनाई जा रही हैं। सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में ग्राम आरोग्य केन्द्र का विस्तार किया जा रहा है। अभी 51 हजार 500 केन्द्रों में ये स्थापित हैं।

प्रदेश के 7 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम

महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के 7 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसका विस्तार आगामी एक वर्ष में पूरे राज्य में किया जाना है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, परिवहन आदि में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्माण किया जाएगा तथा सामुदायिक जागरूकता लाई जाएगी।

मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश अव्वल

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना में प्रदेश में 152 प्रतिशत उपलब्धि हुई है।

लगभग 400 लाड़ली लक्ष्मी11वीं एवं 12वीं कक्षा में

अधिकारियों ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जिन बालिकाओं को लाभ दिया गया था उनमें से लगभग 400 बालिकाएं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में आ गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि इन बालिकाओं की उच्च शिक्षा एवं कॅरियर निर्माण आदि पर ध्यान दिया।

इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्यूंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी हैं।
– अब्दुल कलाम

मुख्यमंत्री मदद योजना के नियमों में संशोधन

भोपाल। आदिम–जाति कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री मदद योजना के नियमों की कुछ कण्डिकाओं में संशोधन किये हैं। इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी किये हैं।

संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री को अब ग्राम पंचायत सचिव प्राप्त कर स्टॉक पंजी में संधारित किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम में अनुसूचित–जनजाति के परिवार में सामाजिक संस्कारों के कार्यक्रम के लिये उक्त सामग्री संबंधित परिवार को निःशुल्क उपयोग के लिये उपलब्ध कराई जायेगी। किये गये संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सामग्री प्रदाय किये जाने की जानकारी संधारित करने के लिये एक पंजी तैयार की जायेगी। उक्त पंजी में समय–समय पर जिस परिवार को उपयोग के लिये सामग्री दी जायेगी, उसका विवरण पंजी में लिखा जायेगा।

मध्यप्रदेश के विभिन्न जन–जातीय समुदाय में जन्म, मृत्यु आदि संस्कारों पर उत्सव करने की परम्परा रही है। इन अवसरों पर सामाजिक भोज का आयोजन परम्परागत रूप से किया जाता रहा है। ऐसे अवसरों पर निर्धनता के कारण कई जन–जातीय परिवार भोज आदि की व्यवस्था में कठिनाई का सामना करते हैं। कई मौकों पर उन्हें ऋणग्रस्तता का सामना करना पड़ता है। जन–जातीय परिवारों को इस समस्या से मुक्त करने के लिये राज्य सरकार ने प्रदेश के 89 जन–जातीय विकासखण्डों में मदद योजना संचालित की है। योजना के अंतर्गत बच्चे का जन्म होने पर उत्सव के लिये 50 किलो अनाज (गेहूँ अथवा चावल) और मृत्यु होने पर भोज के लिये एक क्विंटल अनाज संबंधित परिवार को निर्धारित दर पर उचित मूल्य की दुकान से उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना में सामूहिक भोज के अवसर पर खाना पकाने के लिये बर्तन आदि व्यवस्था के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित ग्राम को 25 हजार रुपये के बर्तन उपलब्ध करवाये गये हैं।

पोल्ट्री फार्म का पंजीयन पशुपालन विभाग में करवाना आवश्यक

सतना। पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसानों एवं पशुपालकों को पशुपालन विभाग में पंजीयन करवाना आवश्यक है। जिससे इसे व्यवस्थित एवं विकसित किया जा सके एवं आवश्यकता होने पर जानकारी के आधार पर तकनिकी सहायता दी जा सके। इस कारण से किसी भी गतिविधि को नियंत्रित करना तथा लाभान्वित करना संभव हो सकेगा। विभाग द्वारा पोल्ट्री उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने तथा विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए वर्तमान में स्थापित तथा नवीन कुक्कुट प्रक्षेत्र हेचरी का पंजीयन प्रारंभ किया गया है, जिससे कुक्कुट प्रक्षेत्र हेचरी की संख्या का सही आंकलन हो सके। भविष्य में लाभकारी नीतियों का निर्धारण अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

मिलावट से मुक्ति अभियान

87 मिलावटखोरों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज

भोपाल। मिलावट से मुक्ति अभियान में खाद्यान्न सामग्री में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। अब तक खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार करने वाले 87 मिलावटखोरों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये गये हैं और 15 मिलावटखोरों पर रासुका के तहत कार्यवाही की गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार करने वाले 25 खाद्य प्रतिष्ठानों को सील किया गया है और 5 खाद्य प्रतिष्ठानों को तोड़कर नष्ट किया गया है।

अभियान के दौरान खाद्य सामग्री में मिलावट पाये जाने पर अनुमानित 5 करोड़ 24 लाख 25 हजार मूल्य की खाद्यान्न सामग्री को जब्त किया गया है। खाद्यान्न सामग्री का कारोबार करने वाले 21 मिलावटखोरों के लायसेंस निबंलित किए गये हैं। मिलावट करने वालों पर 2 करोड़ 60 लाख 45 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियान के तहत अब तक जांच दलों द्वारा 14 हजार 220 स्थानों पर निरीक्षण किया गया है। जाँच के लिये 5719 लीगल नमूनों लिये गये है। राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 2968 नमूनों की जाँच रिपोर्ट जारी की गई। इनमें 668 नमूने अवमानक स्तर के पाये गये, जिन पर कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त चलित प्रयोगशाला के माध्यम से 16 हजार 724 और मैजिक बॉक्स के माध्यम से 23 हजार नमूनें लिये गये। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले के सभी जांच दलों के अधिकारियों को अभियान में और तेजी लाने के लिये कहा गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध सख्ती के साथ कार्यवाही करते हुए अभियान लगातार जारी है।

पोषण वाटिकाओं (किचन गार्डन) का नाम होगा 'माँ की बगिया'

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 2500 किचन शेड एवं 7100 पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण किया

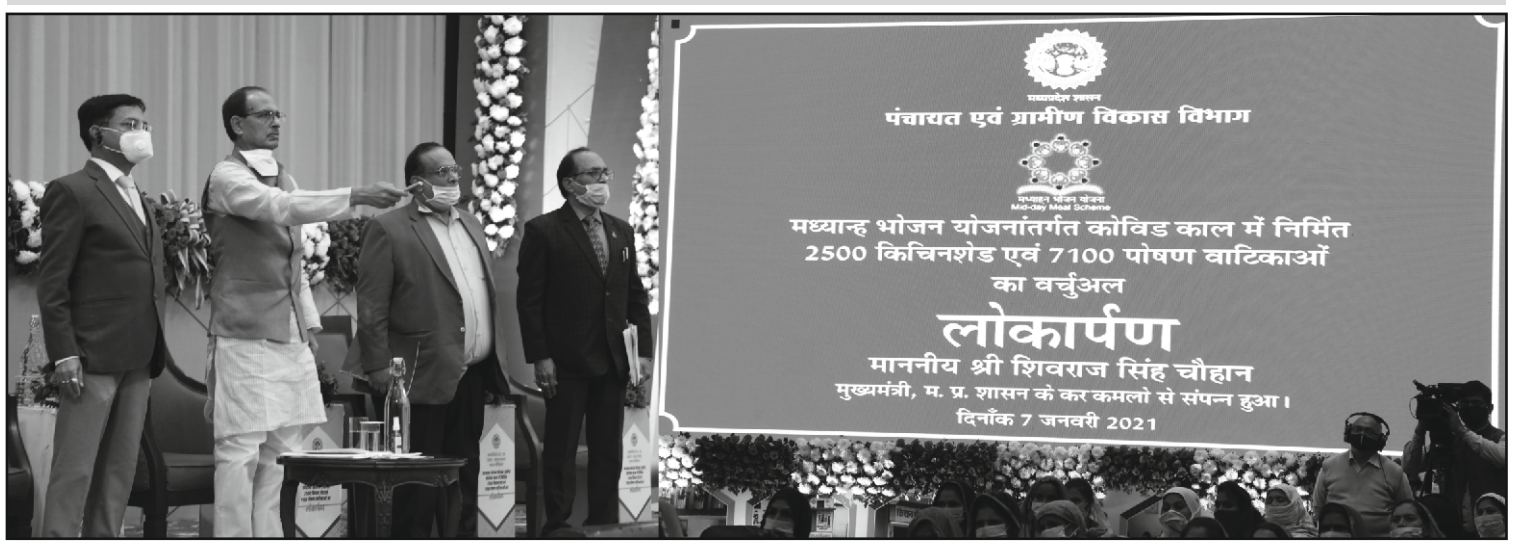

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा के कन्वर्जेन्स से हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका (किचन गार्डन) बनवाए जाएंगे। स्कूलों में जगह न होने पर गांव में अन्य स्थान पर भी पोषण वाटिका बनाई जा सकती है। अब पोषण वाटिका का नाम ''माँ की बगिया'' होगा। स्कूल की स्वच्छता एवं माँ की बगिया के विकास एवं संरक्षण में विद्यार्थियों का पूरा योगदान लिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मिंटो हॉल से प्रदेश में निर्मित 2500 किचन शेड और 7100 पोषण वाटिकाओं के लोकार्पण उपरांत संबोधन दे रहे थे। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव उपस्थित थे।

हम तो अपने स्कूल में झाड़ू लगाते थे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पहले बच्चे अपने स्कूल में स्वच्छता तथा स्कूल की तरक्की में अपना पूरा योगदान देते थे। हम तो अपने स्कूल में झाड़ू लगाते थे। स्कूल की स्वच्छता आदि के काम में कोई शर्म नहीं है। विद्यार्थियों को यह काम करना चाहिए।

भोजन हितभुक, मितभुक और ऋतुभक हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोजन हितभुक अर्थात शरीर के लिए लाभदायी, मितभुक अर्थात सीमित मात्रा में तथा ऋतुभुक अर्थात मौसम के अनुरूप होगा, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्कूल में पोषण वाटिका बनाने का उद्देश्य है बच्चों को ताजी व अच्छी सब्जियां मध्यान्ह भोजन के लिए मिल सकें।

सरपंच, रसोइये, शिक्षक पालक संघ से संवाद किया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में बालाघाट जिले के ग्राम जंगलटोला की सरपंच श्रीमती गुणवंता बिसेन, ग्वालियर जिले के ग्राम उटीला (मुरार) के शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र बघेल तथा गायत्री देवी से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अच्छा किचन शेड निर्माण के लिए उन्हें बधाई दी।

'माँ की बगिया' ही उपयुक्त नाम है

मुख्यमंत्री श्री चौहान को भोपाल जिले के फंदा की प्राथमिक शाला, सिंकदराबाद की स्व–सहायता समूह की रसोइया श्रीमती सुनीता मारन ने बताया कि उन्होंने स्कूल में बनाई गई पोषण वाटिका का नाम श्माँ की बगियाश रखा है। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह उपयुक्त नाम है। अब प्रदेश की सभी पोषण वाटिकाओं को **माँ की बगिया** कहा जाएगा। मैं सी. एम. हाऊस के किचन गार्डन का नाम भी **माँ की बगिया** रखूंगा।

मेहनत
वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है

उद्यानिकी मंत्री श्री कुशवाह ने विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा की

भोपाल। उद्यानिकी, खाद्य प्र–संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और उद्यानिकी कृषकों के कल्याण की योजनाओं के अंतिम ड्रॉफ्ट को जल्द तैयार करें। राज्य मंत्री श्री कुशवाह मंत्रालय में विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि किसानों को खेत की फैंसिंग करने के लिये बनाई जा रही खेत चैन फैंसिंग योजना, किसानों को उनकी फसलों के उत्पादन का भण्डारण करने के लिये खेत पर कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये और छोटे–छोटे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिये तैयार की जा रही योजनाओं के अंतिम ड्रॉफ्ट को जल्द पूरा करें। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव उपस्थित थीं।

मटर उत्पादक किसानों को होगा अधिक मुनाफा

जबलपुर। जबलपुर का स्वादिष्ट हरा मटर न केवल स्थानीय बल्कि अन्य राज्यों और देश की सीमा के बाहर भी लोगों के भोजन का स्वाद बढ़ा रहा है। इसलिए इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी पहल एक जिला–एक उत्पाद योजना के तहत कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने चिन्हित कर जिले में मटर उत्पादन के वर्तमान रकवे में वृद्धि, अच्छे किस्म के बीजों की बोनी व मटर के प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया हैं। साथ ही इसके विपणन नेटवर्क को व्यापक स्वरूप देकर जबलपुर के मटर की ग्लोबल ब्रांडिंग भी की जायेगी। इससे जिले के मटर उत्पादक किसानों को पहले से कहीं अधिक मुनाफा होगा।

अपनी गुणवत्ता और मिठास की वजह से जबलपुर का मटर देश की मंडियों में हाथों–हाथ बिकता है। आलम यह है कि बड़े शहरों के बड़े व्यापारी किसानों से सीधे मटर खरीदकर बाहर इसकी सप्लाई कर रहे हैं। अभी जिले में उत्पादन का 80 फीसदी मटर बाहर जाता है। इस मटर की अधिकाधिक मात्रा को जिले में ही प्रसंस्कृत कर बाहर भेजने की योजना तैयार की गई है।

रबी सीजन में जिले के दो विकासखंडों शहपुरा एवं पाटन के किसान मटर की खेती को प्राथमिकता देते हैं। यहां के तकरीबन 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में दो लाख 30 हजार मीट्रिक टन मटर का उत्पादन किया जाता है। जिले के सिहोरा, मझौली और जबलपुर विकासखंडों के आंशिक क्षेत्रों में भी मटर की खेती होती है।

वर्तमान में जबलपुर का मटर देश की नामचीन मंडियों जैसे मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, नागपुर और रायपुर के अलावा सात समुंदर पार जापान और सिंगापुर के लोगों के व्यंजनों का जायका बढ़ा रहा है। जिले में अभी निजी क्षेत्र की दो मटर प्रसंस्करण यूनिट कार्यरत है। इनमें से भानु फार्मस शहपुरा से प्रतिवर्ष 5 से 8 हजार मीट्रिक टन मटर प्रोसेसिंग की जाती है, यहीं से प्रोसेस्ड मटर सिंगापुर और जापान भेजा जाता है। दूसरी यूनिट फ्रोजन एग्रो इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र उमरिया–डुंगरिया में स्थापित है।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मटर उत्पादक किसानों, उद्यमियों और मटर प्रसंस्करण इकाईयों के संचालकों के साथ हाल ही में कार्यशाला कर एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिले में मटर की फसल के चयन की जानकारी दी और इसके व्यापक उत्पादन और मार्केट लिंकेज पर चर्चा की। कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले के मटर उत्पादक किसानों, प्रोसेसिंग यूनिट, थोक व फुटकर व्यापार से संबद्ध लोगों, निर्यातक, कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगाने के इच्छुक उद्यमियों का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर एक प्लेटफार्म पर लाने का अभिनव कार्य किया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि मटर से लोगों को खेत से मंडी तक काम मिलता है, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने का अवसर बढ़ेगा। मटर की तुड़ाई, ढुलाई और बाहर परिवहन के साथ–साथ सब्जी ठेला और रेहड़ी व्यापारियों को भी काम मिलता है। साथ ही मटर प्रसंस्करण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने से रोजगार के और अवसर बढ़ेंगे।

महिला–बाल विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी
अब ऑन-डिमांड रेडियो एप में उपलब्ध

सतना। मध्यप्रदेश जैसे भौगोलिक रुप से विशाल एवं खाद्य विविधता वाले राज्य में सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में स्थानीय भाषा/बोली में संदेशों का आदान–प्रदान हितग्राहियों, आमजनों के व्यवहार परिवर्तन में सहयोगी हो सकता है। कोविड–19 की वजह से वर्ष 2020 हम सबके लिये चुनौतीपूर्ण रहा है। इस चुनौती ने हम सबको आत्मनिर्भर बनने और संवाद के नये साधनों को विकसित करने का मौका भी दिया है।

इसी के दृष्टिगत और वोकल फॉर लोकल की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग, विभागीय योजनाओं, संदेशों के प्रचार–प्रसार तथा व्यवहार परिवर्तन हेतु एंड्रायड एप दहदूंकप.तंकपव तैयार किया गया है। यह ऑन–डिमांड रेडियो एप प्ले स्टोर पर दहदूंकपण्तंकपव के नाम से उपलब्ध है जहाँ से इसे मोबाइल में डॉउनलोड किया जा सकता है। संभवतः मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है जहां किसी शासकीय विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं, संदेशों के प्रचार–प्रसार तथा व्यवहार–परिवर्तन के लिये इस तरह की नवीन टेक्नॉलाजी का उपयोग करते हुए ऑन–डिमांड रेडियो एप तैयार किया गया है।

आँगनवाड़ी रेडियो का मुख्य उद्देश्य हितग्राही किशोरी बालिकाओं, महिलाओं के साथ ही आम–जनों तक स्वास्थ्य, पोषण, विभागीय कार्यक्रमों, गतिविधियों व योजनाओं की जानकारियां और संदेश ऑडियो फॉरमेट में पहुँचाना है। यह हिन्दी भाषा के साथ ही स्थानीय बोलियों (भीली, गोंडी, कोरकू, बुन्देलखंडी आदि) में भी रहेगी। स्थानीय बोलियों में संदेशों का आदान–प्रदान करने से आँगनवाड़ी रेडियो व्यवहार परिवर्तन में सहयोगी माध्यम साबित होगा।

आँगनवाड़ी रेडियो के माध्यम से संदेश, जिंगल, नाटक, कहानी, प्रश्नोत्तरी आदि ऑडियो केटेगरी के अंतर्गत पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विकास, महिला सषक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि विषयों को सुन सकते हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ता इन जानकारियों को क्षेत्रवार भी सुन सकते हैं। बच्चे रोचक एवं शिक्षाप्रद कहानियां भी सुन सकेंगे।

नए साल में मध्यप्रदेश को नंबर एक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करें

नए वर्ष में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताए शासन के प्रमुख सूत्र तथा प्राथमिकताएँ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण सहित सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए नए साल में सभी समर्पण भाव से जुट जाएं। बिना लिए–दिए समय–सीमा में जनता को सेवाएं प्राप्त कराना सुशासन का मूलमंत्र है, जिसे हमें प्रदेश में चरितार्थ करना है। इसके लिए तकनीकी का भी पूरा उपयोग किया जाए। प्रदेश में एक अच्छा फीडबैक सिस्टम तैयार करना है। हमारा प्रशासन सज्जनों के लिए फूल की तरह कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से भी अधिक कठोर होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रीगणों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए शासन के सूत्र एवं प्राथमिकताएँ बताईं। उन्होंने सभी को नए साल की शुभकामनाएं भी दीं।

ये होंगे शासन के 12 प्रमुख सूत्र

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रशासन के 12 प्रमुख सूत्र बताते हुए कहा कि हमारा पहला सूत्र है कि जनता ही अपनी भगवान है। कोई भी अहंकार में न रहे तथा जनता की सेवा एवं बेहतरी के लिए कार्य करें।

दूसरा सूत्र है – मध्यप्रदेश के खजाने पर सबसे पहले गरीबों का हक है। गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

किसान एवं कृषि का विकास हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिन्दु है। किसानों की फसल की उत्पादन लागत घटाने तथा उन्हें फसलों का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए निरंतर कार्य करना है। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जाने हैं।

चौथा सूत्र है – महिला सशक्तीकरण। हमें महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक सशक्तीकरण करना है तथा उन्हें पूरा सम्मान एवं सुरक्षा देनी है। महिला स्व–सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। बेटियों की सुरक्षा के लिए हम धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 लाए हैं।

पाँचवा सूत्र है – प्रदेश में सुशासन देना, जिसके अंतर्गत जनता को निश्चित समय–सीमा में सेवाएं बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए तथा बिना कुछ लिए–दिए प्राप्त हो जाएं।

छठवां सूत्र है – प्रदेश को माफिया मुक्त करना। प्रदेश में ड्रग माफिया, मिलावट माफिया, भू–माफिया, रेत माफिया आदि के विरूद्ध सघन अभियान जारी रहेगा। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि आमजन को कोई दिक्कत न हो। किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में न फंसाया जाए।

सातवाँ सूत्र है – परियोजनाओं को निश्चित समय पर पूरा करना। इसके लिए मैं स्वयं हर हफ्ते बड़ी योजनाओं की समीक्षा करूंगा, मंत्रीगण भी नियमित समीक्षा करें। अधिकारीगण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। परियोजनाएं बिना लागत बढ़े समय से पूरी हो जाएं।

आठवां सूत्र है – केन्द्र की हर योजना में नंबर वन रहना। इसके लिए सभी निरंतर प्रयास करें। मंत्रीगण केन्द्र से निरंतर समन्वय रखें तथा दिल्ली के दौरे करें। विभिन्न योजनाओं में केन्द्र से अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं।

नौवां सूत्र है – आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का गठन। इसके लिए बनाए गए रोडमैप पर तेजी से क्रियान्वयन किया जाए।

दसवां सूत्र है – अधिक से अधिक रोजगार सृजन। इसके लिए हर विभाग प्रयास करे। शासकीय व अशासकीय दोनों क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित किए जाएं। कौशल विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए।

ग्यारहवां सूत्र है – जन स्वास्थ्य। हमें प्रधानमंत्री जी के दोनों मंत्र ''स्वास्थ्य ही संपदा'' है और ''दवाई भी कड़ाई भी'' का पालन करना है। हमें अपने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को उच्च कोटि का बनाना है। साथ ही फीवर क्लीनिक को इस प्रकार विकसित करना है कि वहां जनता को हर प्रकार के रोगों का प्राथमिक इलाज मिल सके।

बारहवां सूत्र है – अच्छी शिक्षा। इसके लिए हमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रत्येक 20–25 किलोमीटर के दायरे में सी.एम. राइज स्कूल खोले जाएंगे। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

> हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हमारे पास समान अवसर हैं, अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए
> – रतन टाटा

कौओं में पाया जाने वाला वायरस मुर्गियों में अभी तक नहीं मिला

भोपाल। पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल के निर्देश पर प्रदेश में हो रही कौओं की मृत्यु पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिये अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कौओं और पक्षियों की मृत्यु की सूचना पर तत्काल रोग नियंत्रण के लिये भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश में 23 दिसम्बर से 3 जनवरी, 2021 तक इंदौर में 142, मंदसौर में 100, आगर–मालवा में 112, खरगोन जिले में 13, सीहोर में 9 कौओं की मृत्यु हुई है। मृत कौओं के सैम्पल भोपाल स्थित स्टेट डी. आई. लैब तत्काल भेजे जा रहे हैं। इंदौर में कंट्रोल–रूम की स्थापना कर रेपिड रिस्पांस टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

पोल्ट्री और प्रवासी पक्षियों की विशेष निगरानी

जिलों में पदस्थ पशुपालन विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि कौओं की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन और अन्य विभागों के समन्वय से तत्काल नियंत्रण एवं शमन की कार्यवाही कर रिपोर्ट संचालनालय भेजें। तत्काल संबंधित स्थल का भ्रमण कर आसपास के क्षेत्रों में भी रोग उदभेद नियंत्रण एवं शमन की कार्यवाही सुनिश्चित करें। पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पाद बाजार, फार्म, जलाशयों एवं प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखते हुए प्रवासी पक्षियों के नमूने एकत्र कर भोपाल लैब को भेजें।

रोग नियंत्रण कार्य में लगे हुए अमले को स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीपीई किट, एंटी वायरल ड्रग, मृत पक्षियों, संक्रमित सामग्री एवं आहार का डिस्पोजल और डिसइन्फेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

बर्ड फ्लू के लक्षण, पक्षियों पर नजर रखें

पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कौओं में पाया जाने वाला वायरस H5N8 अभी तक मुर्गियों में नहीं मिला है। मुर्गियों में पाया जाने वाला वायरस सामान्यतरू H5N1 होता है। श्री पटेल ने लोगों से अपील की है कि पक्षियों पर नजर रखें। यदि पक्षियों की आँख, गर्दन और सिर के आसपास सूजन है, आँखों से रिसाव हो रहा है, कलगी और टांगों में नीलापन आ रहा है, अचानक कमजोरी, पंख गिरना, पक्षियों की फुर्ती, आहार और अंडे देने में कमी दिखाई देने के साथ असामान्य मृत्यु दर बढ़े, तो सतर्क हो जायें।

सोलर एनर्जी के उपयोग को जन आंदोलन बनाएं : श्री चेतन सिंह सोलंकी

भोपाल। एनर्जी स्वराज्य मिशन के ऊर्जा विशेषज्ञ प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने सोलर एनर्जी के उपयोग को जन आंदोलन बनाने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर रही है। यह दशक तय करेगा कि पृथ्वी के समक्ष मौजूदा संकटों और चुनौतियों से निपटने में हम कितने समर्थ हो पाएँगे। ग्लोबल वार्मिंग–जलवायु परिवर्तन रोकना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रोफेसर श्री सोलंकी ने कहा कि परंपरागत ईंधनों के अंधाधुंध उपयोग और औद्योगिक गतिविधियों के कारण कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस समझौते के अंतर्गत तमाम कामों के बावजूद हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं हुआ है। कार्बन के इस बोझ को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाकर कम किया जा सकता है। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्त्रोत सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी के बढ़ावे से बहुत हद तक प्रकारांतर से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। प्रोफेसर सोलंकी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय स्थित पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर में "सोलर एनर्जी और पर्यावरण" विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। इस अवसर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले एवं बिजली इंजीनियर मौजूद थे।

खरगोन जिले को मिला डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम पुरस्कार

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने ऑनलाइन कार्यक्रम में वितरित किये डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा संचालित प्रवासी श्रमिक और रोज़गार सेतु पोर्टलों को 'महामारी में नवाचार' श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समारोह डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पोर्टल COVID–19 महामारी के दौरान प्रवासी और अन्य श्रमिकों की पहचान, पंजीकरण, कौशल और रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किए गए हैं। जिला खरगोन को जिले की वेबसाइट के लिए 'डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता – जिला' श्रेणी के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय विधि और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, सचिव (MEITY) श्री अजय साहनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति विज्ञान भवन, नई दिल्ली और भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और विभिन्न स्थानों से पुरस्कार समारोह में

शामिल हुए।

ये पोर्टल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हैं और मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने COVID–19 महामारी के दौरान इस तरह की योजना को लागू किया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड की 'महामारी में नवाचार' श्रेणी ऐसी सरकारी संस्था का सम्मान करती है, जिसने संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा जैसे क्षेत्रों में महामारी के दौरान नागरिकों को विभिन्न गतिविधियों को आसानी से पूरा करने के लिए उत्कृष्ट, अभिनव और डिजिटल समाधान विकसित किया हो अथवा सरकारी सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की हो। मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक पोर्टल और श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप ने COVID–19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की पहचान और पंजीकरण में मदद की। इस पोर्टल द्वारा बनाए गए प्रवासी श्रमिकों के एकीकृत डेटाबेस का उपयोग सरकारी विभागों और जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए किया जा रहा है। रोज़गार सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रवासी और अन्य श्रमिकों को उनके कौशल और पूर्व अनुभव के आधार पर उनके अपने गाँव और शहर में रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुरस्कार श्रेणी 'डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता – जिला' में जिला प्रशासन की उन उपलब्धियों को पुरस्कृत किया जाता है जिसने नागरिकों को क्षेत्रीय भाषा में व्यापक जानकारी प्रदान करने पर अनुकरणीय ध्यान केंद्रित किया है। खरगोन की जिला वेबसाइट को नागरिक केंद्रित आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रामाणिक और विश्वसनीय एकल खिड़की सूचना प्रसार प्रणाली होने के लिए प्लैटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह वेबसाइट दिव्यांग–अनुकूल होने के साथ–साथ जिले के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे पर्यटन, कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और उपयोगिताओं तक पहुंच को प्रदर्शित करती है। इस वेबसाइट पर सूचना अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

छः श्रेणियों में से 2 मध्यप्रदेश के खाते में

डिजिटल इंडिया अवार्ड डिजिटल–गवर्नेंस में अनुकरणीय पहलों और प्रथाओं को सम्मानित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 की घोषणा छरू श्रेणियों में की गई है – महामारी में नवाचार; डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता– केंद्रीय मंत्रालय/विभाग; डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता– राज्य/केंद्रशासित प्रदेश; डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता– जिला; ओपन डेटा चैंपियन; और अनुकरणीय उत्पाद। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर से शुरू हुई और एक महीने के लिए जारी रही। इस दौरान 402 नामांकन प्राप्त हुए। नामांकन की शॉर्टलिस्टिंग और रैंकिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली द्वारा की गयी। प्रत्येक श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किए गए नामांकन की ऑनलाइन प्रस्तुतियों को मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय जूरी के समक्ष पेश किया गया और उसके बाद अंतिम विजेता का चुनाव हुआ।

(पृष्ठ 1 का शेष)

जिले बनाएं विकास योजनाएँ.....

उन्होंने कहा कि खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। खरीदी पश्चात बिलिंग एवं भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जाये। जहां बाजरे के भुगतान की स्थिति संतोषप्रद नहीं है वे जिले तत्काल भुगतान की कार्यवाही करें। जिन जिलों में परिवहन की गति धीमी रही है अथवा स्वीकृतियों में विलंब हुआ है वे इस पर ध्यान दें। खरीदी केंद्रों पर छोटे एवं बदरंग दाने आने के कारण खरीदी को ना रोका जाए और किसानों की फसल खरीदी जाए। जिन खरीदी केंद्रों पर तुलाई के लिए पैसों की मांग की जा रही है अथवा तुलाई में गड़बड़ी की जा रही है वहां ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ऐसे उपाय करें जिससे तुलाई केंद्रों पर किसानों से तुलाई और लोडिंग का पैसा ना लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धान खरीदी और ज्वार, बाजरे की स्थिति जिलों से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान मित्र सरकार है। उन्होंने धान, ज्वारे, बाजरा खरीदी में अच्छा कार्य करने वाले कुछ जिलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स मौसम को देखते हुए धान की सुरक्षा करें, अस्थायी केब का प्रबंध करें।

अनियमितताओं पर हुई कार्यवाही

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 08 जिलों में खाद्यान्न उपार्जन में अनियमितताएं होने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। कुल 32 एफ. आई.आर. कर 55 संस्थाओं और व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। लगभग 05 हजार क्विंटल धान जप्त किया गया। प्रदेश में 32 वाहन भी जप्त किए गए हैं। रीवा में 16 वाहन जप्त किए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए रीवा कलेक्टर को बधाई दी। कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 03 जनवरी तक 25 लाख 39 हजार 613 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसी तरह ज्वार और बाजरा भी करीब सवाल दो लाख मीट्रिक टन खरीदा जा चुका है। कुल 4.28 लाख किसानों से खरीदी हुई। इन्हें भुगतान का कार्य भी हो चुका है। कुल 87 प्रतिशत परिवहन हो गया है। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि भारत सरकार के अधिकारियों ने ग्वालियर, जबलपुर संभाग भ्रमण कर धान की गुणवत्ता भी देखी जो संतोषजनक है। ग्वालियर, चंबल संभाग को छोड़कर शेष संभागों में धान खरीदी 16 जनवरी तक चलेगी। प्रदेश में 1417 उपार्जन केन्द्रों के लिए 1747 गुणवत्ता सर्वेयर पंजीबद्ध हैं। ज्वार और बाजरा का उपार्जन कार्य पूरा हो गया है। उपार्जन कार्य में पाँच जिलों का प्रदर्शन श्रेष्ठ हैं जिनमें होशंगाबाद, नरसिंहपुर, पन्ना, बैतूल और रायसेन शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शेष जिलों को अपेक्षित प्रगति के प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने धान के भंडारण और बारदाना व्यवस्था की भी जानकारी ली।

मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी भी स्थिति में मिलावट करने वालों को न बख्शें। मटर में हरा रंग, मिर्च में लाल रंग घातक है। आलू में एसिड मिलने का काम इंदौर में हो रहा था। इन मामलों का स्वास्थ्य विभाग फालोअप करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में मिलावट के लिए दोषी फैक्ट्री तोड़ी गई, ये अच्छी कार्यवाही है।

समय पर खाद्यान्न न बांटना पाप है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समय पर खाद्यान्न का वितरण न करना अपराध है, एक तरह का पाप है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करें। श्री चौहान ने सतना में उपभोक्ता भंडार संचालक पर की गई कार्यवाही की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही अन्य जिले भी सतत रूप से करें। खाद्यान्न की कालाबाजारी गरीबों के पेट पर लात मारने का जुर्म है। ऐसे अपराधियों को बिल्कुल न छोड़ें।

भू–माफियाओं से मुक्त करना है मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कानून, व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश को माफिया मुक्त करना है। उन्होंने कांफ्रेंस में साफ शब्दों में दोहराया कि गरीबों को कहीं परेशान न होना पड़े, यह सुनिश्चित करें। अतिक्रमण के नाम पर सामान्य व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही न हो। गुंडे, रसूखदार के विरुद्ध हो एक्शन अवश्य लिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश पुलिस को चिट फंड कंपनियों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बधाई दी। प्रदेश में करीब पांच लाख नागरिकों को उनकी डूबी राशि वापस मिल गई है। कुल 825 करोड़ रुपये की राशि निवेशकों को मिल सकी।

सायबर क्राइम पर नजर रखें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सायबर क्राइम के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि सायबर क्राइम पर रोकथाम हो, अलग काल सेंटर बनाएं। सायबर क्राइम के लिए जन जागरूकता भी बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सायबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम जन भी सजग हों। पुलिस स्टाफ को भी दक्ष किया जाए।

आधारित साधनों का उपयोग कर ऐसे अपराधों के पैटर्न की जानकारी प्राप्त कर प्रत्येक स्तर पर सजगता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरुरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरुरी है

नागरिकों को मोबाइल पर सेवाएं देने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन में किया समस्याओं का त्वरित निराकरण

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन के लिए जनता को शासकीय योजनाओं का समय पर लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि उन्हें इनका लाभ मिलने में विलंब होता है तो विलंब के लिए जिम्मेदार शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑनलाइन राशि समय पर अंतरित किए जाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सी.एम. हेल्पलाइन 181 के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र एक ही दिन में दिए जाने की सुविधा प्रदान करने वाला म.प्र. देश का पहला राज्य है। सी.एम. हैल्पलाइन में नागरिक अब अपनी शिकायतें व्हॉटसएप नंबर 7552555582 पर भी दर्ज करवा सकते हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी भी उपस्थित थे।

सी.एम.ओ. और लिपिक को निलंबित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिवपुरी जिले के एक प्रकरण में शासकीय योजना की किश्त देने में हितग्राही (श्री दामोदर प्रसाद) को विलंब किए जाने की शिकायत पर तत्कालीन सी.एम.ओ. और लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।

दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान को मंडला जिले के आवेदक श्री देवेन्द्र ने बताया कि उसकी बहन 2018 से लापता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तुरंत उसे ढूंढने की कार्रवाई करने तथा दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए।

फसल बीमा की राशि सभी किसानों को मिले

मुख्यमंत्री श्री चौहान को शाजापुर जिले के आवेदक श्री मनोज राजपूत ने बताया कि उसे फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि फसल बीमा योजना का लाभ हर प्रभावित किसान को दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली, प्राचार्य को निलंबित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान को दतिया की कुमारी श्रद्धा पिता राधेश्याम ने बताया कि उसे ष्मांव की बेटी योजनाष् के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कार्य में लापरवाही करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य के निलंबन की कार्रवाई करें।

पट्टा देने के लिए प्रशासन को बधाई

बड़वानी जिले के आवेदक श्री बद्री ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसे जमीन का पट्टा दिलवाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आवेदक की समस्या समझने तथा त्वरित कार्रवाई कर उसे पट्टा देने के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी।

सहायता में न हो विलंब

मुख्यमंत्री श्री चौहान को रायसेन जिले के जय सिंह बंजारा ने बताया कि बेटे की मृत्यु के उपरांत उन्हें सहायता मिलने में बहुत विलंब हुआ। अब उन्हें सहायता मिल गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य में विलंब के लिए संबंधित पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए।

समय पर मिले जमीन का मुआवजा

मुख्यमंत्री श्री चौहान को रीवा जिले के किसान श्री भगवत सिंह ने बताया कि उन्हें बाणसागर परियोजना में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिलने में देरी हुई है। कलेक्टर ने बताया कि लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण करते हुए 194 किसानों को मुआवजा दिला दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विलंब के संबंध में संबंधित एस.डी.एम. से कारण पूछे जाने के निर्देश दिए।

पूरी राशि एक साथ दी जाए

इंदौर जिले में बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा द्वारा स्ट्रीट वेण्डर योजना के अंतर्गत 10 हजार के स्थान पर 05–05 हजार रूपए दिए जाने की शिकायत पर संबंधित बैंक मैनेजर ने बताया कि दस्तावेजों के पूरे न होने के कारण दो किश्तों में राशि दी जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत पूरी राशि 10 हजार रूपए एक साथ प्रदाय की जाए।

उच्च प्रदर्शन वाले जिलों की सराहना की

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सी.एम. हेल्पलाइन में समस्याओं के निराकरण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले सिवनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, छतरपुर, देवास, बुरहानपुर, होशंगाबाद, डिण्डौरी, झाबुआ तथा रतलाम की सराहना करते हुए कलेक्टर्स को बधाई दी। वहीं खराब प्रदर्शन वाले जिलों रायसेन, मुरैना, भिण्ड, इंदौर, शिवपुरी, शाजापुर, खरगौन, बड़वानी, धार तथा आगर–मालवा को कार्य सुधारने के निर्देश दिए गए।

> सफल लोग
> कोई अलग काम
> नहीं करते,
> वो बस अलग
> तरीके से
> काम करते हैं
> — **शिव खेड़ा**

अधिक दर पर गिरवी रखे वाहनों को सूदखोर माफिया से कराया मुक्त

भोपाल। एंटी माफिया अभियान के तहत सूदखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन एवं पुलिस देवास द्वारा कार्यवाही कर जप्त की गई 25 मोटर साइकिल, एक चार पहिया वाहन, मकानों एवं अन्य संपत्ति न्यायालय के आदेश के बाद वाहन स्वामियों को सुपुर्द कर दिये गये हैं।

कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार जिले में सभी प्रकार के माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह के नेतृत्व में विशेष अभियान के तहत भू–माफिया, रेत माफिया, नशा मुक्ति, सूदखोर, मिलावटखोर एवं महिला संबंधी अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस विभाग की टीम गठित की गई। सूदखोरों के खिलाफ कार्यवाही कर अपराध धारा 384, 506, 34 भावदि एवं 3/4 म.प्र ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस द्वारा आरोपी सुरेश पिता नन्नूलाल एवं कपिल पिता नन्नूलाल रैकवार निवासी जय भारत नगर भैरूगढ़ देवास को गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों के घर पर रखे हुए वाहन जप्त किये गये। आरोपियों द्वारा लोगों को ऊँचे ब्याज दर पर रकम दी जाती थी और मूल से कई गुना ज्यादा ब्याज दर वसूल कर डरा धमकाकर लोगों से पैसे, मोटर साइकिल व अन्य वाहन अपने कब्जे में ले लेते थे।

सूदखोर माफिया के विरूद्ध की गई कार्यवाही में 25 मोटर साइकिल, एक चार पहिया वाहन, मकानों एवं अन्य संपत्ति जिसकी कीमत 25 लाख रूपये अनुमानित है, जब्त की गई। पुलिस द्वारा सभी वाहन स्वामियों को न्यायालय के आदेश के पालन में सुपर्दुगी पर वापस किए गये हैं। आरोपियों के पास गिरवी रखी अन्य चल–अचल संपत्ति की भी जानकारी ली जा कर मुक्त कराने की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के कार्यों का रोडमैप तैयार करने के लिए समिति का गठन

भोपाल। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश वर्ष 2023 की कार्य योजना एवं नीति बनाने के लिए स्कल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है।

गठित समिति आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यो का स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव पर अपनी अनुशंसाए दिसम्बर 2021 तक सौपेंगी। यह समिति आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत की अध्यक्षता में गठित की गई है। समिति के अन्य सदस्यों में आयुक्त, आदिम जाति विकास श्री संजीव सिंह, उपसचिव लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव आदिम जाति कल्याण विभाग श्री दिनेश श्रीवास्तव, अपर संचालक लोक शिक्षण सुश्री कामना आचार्य, अपर संचालक, आदिवासी विकास श्री विक्रमादित्य सिंह, संचालक लोक शिक्षण श्री डी.के. कुशवाह, अपर संचालक लोक शिक्षण श्री के.के. व्दिवेदी, उपायुक्त आदिवासी विकास श्रीमती सीमा सोनी शामिल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 128 करोड़ रुपये लागत के लाइट हॉउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी

मुख्यमंत्री श्री चौहान इंदौर से कार्यक्रम में हुये शामिल

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश के इंदौर सहित छह राज्यों के छह स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज– इंडिया (जीएचटीसी– इंडिया) के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं (लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स) की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेरेटर्स– इंडिया (एएसएचए– इंडिया) के तहत विजेताओं की भी घोषणा की और प्रधानमंत्री आवास योजना– शहरी (पीएमएवाई–यू) मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2019 के वार्षिक पुरस्कार भी दिये। मध्यप्रदेश को उल्लेखनीय कार्य के लिये दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वर्चुअल रूप से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रदेश के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आज नये वर्ष का पहला दिन एक जनवरी, 2021 उपलब्धि भरा रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में 128 करोड़ रूपये लागत की लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री तुलसीराम सिलावट, श्री आकाश विजयवर्गीय तथा श्री महेन्द्र हार्डिया शामिल हुये। कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश को उक्त पुरस्कार प्राप्त होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में आवासहीनों के लिये आवास निर्माण बनाने में नई तकनीकों का उपयोग शुरू किया गया है। इससे कम लागत में, कम समय में गुणवत्तापूर्ण आवास निर्मित होंगे। नई तकनीकों के उपयोग के लिये विभिन्न नवाचार किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लाईट हाउस प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिये नवोन्मेषी निर्माण के लिये 54 नवोन्मेषी आवास निर्माण प्रौद्योगिकी चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार निर्माण क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) उपयोग में लाये जायेंगे। जो की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकी, सामग्रियों और प्रक्रियाओं का बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं। इनका निर्माण जीएचटीसी– इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो आवास निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक समग्र परिवेश तैयार करने की परिकल्पना है। ये परियोजनाएं पारंपरिक तौर पर ईंट एवं कांक्रीट वाले निर्माण के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से पूरी होंगी। इसके अलावा ये मकान उच्च गुणवत्ता के साथ किफायती और टिकाऊ भी होंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम, राजकोट के एलएचपी में टनल फॉर्मवर्क का उपयोग करते हुए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, चेन्नई की परियोजना में प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, रांची के एलएचपी में 3डी वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, अगरतला की परियोजना में लाइट गेज स्टील इन्फिल पैनलों के साथ ढांचागत स्टील फ्रेम और लखनऊ के एलएचपी में पीवीसी स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम से आवास निर्माण किये जायेंगे। हल्के मकानों की परियोजनाएं संबंधित जगहों पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण एवं उसके अनुकरण की सुविधा के लिए एक लाइव प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं बहुत उपयोगी हैं। उन्होंने आईआईटी, एनआईटी, अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों और प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कॉलेजों के संकाय के छात्रों से कहा कि वे इन परियोजनाओं का अध्ययन करें तथा इन्हें और अधिक बेहतर तथा उपयोगी बनाने के लिये अपने सुझाव दें तथा उसमे नवाचार करें। प्रोजेक्ट के तहत उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और सामग्रियों से रचनात्मक मस्तिष्क वाले युवाओं, स्टार्ट–अप, इनोवेटर और उद्यमियों को भी मदद मिलेगी।

योजना आवासहीनों के लिये एक उपहार है–मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा लिये गये सभी को पक्के मकान देने का संकल्प प्रदेश में 2022 तक पूरा कर लिया जायेगा। प्रदेश में तेजी से आवास निर्माण किये जा रहे हैं। यह योजना आवासहीनों के लिये एक उपहार है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निर्मित आवासों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराईं जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 378 निकायों में अभी तक सात लाख 24 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से तीन लाख आवासों का निर्माण पूरा हो गया है। दो लाख आवासों का निर्माण प्रगति पर है। एक लाख से अधिक आवास आवंटित भी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि आवासों का निर्माण पूरा करने के लिये तेजी से काम चल रहा है। निर्धारित समय–सीमा में आवासों का निर्माण पूरा कर लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों को आवास आवंटित कर दिये जायेंगे।

नई तकनीक से आवास बनाना क्रांतिकारी पहल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के माध्यम से नई तकनीक से आवास बनाना क्रांतिकारी पहल है। इसके तहत बने आवास आपदारोधी, पर्यावरण के अनुकूल तथा गुणवत्तापूर्ण रहेंगे। ये कम समय में भी तैयार होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह गौरव की बात है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का भी चयन हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में 128 करोड़ रूपये की लागत से नवीन तकनीक पर आधारित एक हजार से अधिक आवास बनेंगे।

आदिम-जाति कल्याण विभाग की शालाओं के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

भोपाल। आदिम–जाति कल्याण विभाग की शालाओं को शैक्षणिक सत्र 2020–21 में सत्र प्रारंभ करने एवं शालाओं के संचालन के संबंध में विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। दिशा–निर्देश गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड–लाइन 30 सितम्बर, 2020 के आधार पर कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जारी किये गये हैं।

बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा–10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिये विद्यालय नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिये संचालित होंगे। विद्यालयों में विद्यार्थियों को इस प्रकार से आमंत्रित किया जायेगा, कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक–साथ अधिक न हो। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता–पिता अथवा अभिभावकों की सहमति पर निर्भर करेगा। विद्यार्थी के लिये दी गई सहमति पूरे सत्र के लिये मान्य होगी। कक्षा–9वीं एवं 11वीं के लिये विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। समय–समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाइन अथवा दूरस्थ शिक्षण अध्यापन की पद्धति के रूप में बना रहेगा। जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।